

प्रयागराज संदेश

महाकुंभ 2025 : मेला प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित ले आउट प्लान की दी गई जानकारी

अखंड भारत संदेश

प्रयागराज। मेला अधिकारी, कुंभ मेला, विजय किरन आनंद ने संघरणथम महाकुंभ - 2025 के दृष्टिकोण से योग्य एवं अनुमति पाने के लिए बैठक की संदेशिक स्वीकृति हेतु अवगत कराया की कुम्भ मेला 2019 की बसवाट 3200 है, में की गयी थी और 22 पानून पुलों का बैठक की संख्या 30 होगी। जो गत कुंभ मेला के सापेक्ष लगभग 800 है, अधिक है, ले आउट प्लान के अनुसार 08 पानून पुल बनाया जाना प्रस्तावित है।

आतिरिक्त पानून पुल बनाया जाना प्रस्तावित है।



गंगा पंडाल बनाया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई तथा शोध समिति के समक्ष अनुमति हेतु प्रेषित किया जाएगा। इसी क्रम में टेटेटज का प्रत्यावर्ती भी सैद्धांतिक सहभागी बने जिसके अंतर्वाले 25000 लोगों के लिए पालबंद अंकोमेंशन तथा 10000 कैपेसिटी का

लगभग 145000 दोयलेट लगाने तथा उपको सफाई हेतु 10000 सफाई कर्मी अवधारणा का प्रस्तावित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 25000 डस्टबिन, 800 सफाई गैंग तथा आईसीटी बेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्रस्तावित किया गया। सभी प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई तथा शोध समिति के स्वीकृति हेतु मोनोदान हेतु प्रेषित किया जाएगा। महाकुंभ 2025 को हारित कुंभ बनाने की दृष्टिकोणात्मक वन अधिकारी द्वारा महाकुंभ से पहले 150000 पेड़ लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया। साथ ही स्थानीय अधिकारी ने एपीएस आइएस ऐपरेल के मायम्य से अनुत्रवण हेतु पीएसआइएस पोर्टल विकासित किये जाने के लिए एजेंसी के आवादीकरण तथा माघ मेला 2023-24 के पश्चात मेला क्षेत्र में 100 अदद एक्सार्टों द्वारा लेट के वर्ष पर्हन आपरेशन एंड मेटेनेंस के साथ स्थापित किए जाने के प्रस्तावों को भी बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई।

संपादक की कलम से

कनाडा जाना बंद करें बच्ये, होश आ जाएगी टूडो को

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने जिस बेशमी से अपने देश के खालिस्तानी आंदोलनकारियों को समर्थन देना शुरू किया है उससे दोनों देशों के संबंध तार-तार जैसे हो गए हैं। भारत-कनाडा संबंधों को मजबूर्ती देने का काम तो भारत से हर साल वहां पर पढ़ने के लिए जाने वाले हजारों-लाखों नौजवान करते रहे हैं। जाहिर है, भारत का आमजनन कनाडा के प्रधानमंत्री के रुख से बहुत खिल्ल है। भारत ने अपने कुटनीतिक जवाब में कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा देने पर रोक लगाया है। दूसरी ओर जो भारतीय छात्र कनाडा जाकर पढ़ना चाहते थे, वे अब ऐसा करने से स्वयं बच रहे हैं। इसकी वजह से भी दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ है। विदेश में पढ़ने जाने के लिए मदद करने वाली एक कंसल्टेंट कंपनी का कहना है कि इसी वर्ष हमारे पास 65 ऐसे छात्र आएं थे, जो कनाडा पढ़ने जाना चाहते थे किंतु, अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि भारत से

हरेक साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कनाडा अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि देशों में बच्चों चले जाते हैं? यह सबाल कनाडा में जो भारत को लेकर हो रहा है उससे पहले ही भारतीयों के साथ हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय अपनी एडवाइजरी जारी कर चुका है। विदेश मंत्रालय भारत में कनाडा के उच्चायाग से इन घटनाओं को कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाने व उनकी सही जांच करवाने के लिए भी कई बार कह चुका है। यह भी सच है कि कनाडा में धृणा अपराधों, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तो निश्चित रूप से बृद्धि हुई है। भारत के लाख कहने के बावजूद कनाडा सरकार वहां पर जा बस, या रह रहे भारतीयों को सुरक्षा प्रदान नहीं करवा पा रही है। कनाडा में अब भी हजारों या यूं कहिये विदेशी भारतीय नौजवान पढ़ रहे हैं। अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। उपलब्ध आकड़ों के अनुसार साल 2018-19 के दौरान ही 6.20 लाख विद्यार्थी पढ़ने के लिए देश से बाहर गए थे। ये आंकड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही जारी किए थे। ये अधिकतर स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के लिए ही कनाडा या किसी अन्य देश का रुख करते हैं स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के लिए बाहर जाने वाले अपेक्षाकृत कम ही होते हैं। पर मूल बात यह है कि हर साल इन विद्यार्थियों के अन्य देशों में जाने के कारण देश की अमल्य विदेशी मुद्रा भी देश के बाहर चर्ल्स जाती है। इन लाखों विद्यार्थियों के लिए देश को अरबों रुपया अन्य देशों को देना पड़ता है वह भी विदेशी मुद्रा में। अगर कोई विद्यार्थी वास्तव में किसी खास शोध आदि के लिए अमेरिका की एमआईटी या कोलोरोर्डे जैसे विश्वविद्यालयों में दाखिला लेता है तो कोई बुराई भी नहीं है। आखिर अमेरिका के कुछ विश्व विद्यालय अपनी श्रेष्ठ फैकल्टी और दूसरी सुविधाओं के चलते सच में बहुत बेहतर हैं। यही बात ब्रिटेन के आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों के संबंध में भी कही जा सकती है। इनमें बहुत से अध्यापक नोबेल पुरस्कार विजेता तक हैं इसलिए इनमें दाखिला लेने में तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हमारे बच्चे होटल मैनेजमेंट या एमबीए या सामान्य स्नातक डिग्री जैसे कोर्सजे के लिए कनाडा, यूक्रेन और चीन जाएं तो बात गले से नहीं उतरती। सच पूछा जाए जाए तो इसका कोई ठोस कारण भी समझ नहीं आता। फिर यह भी एक तथ्य है कि विदेशों में पढ़ाई के लिए जाने वाले बच्चों को अनेक अवसरों पर घोर कष्ट भी होता है। उन्हें कई बार विदेशी विश्वविद्यालयों सञ्चालन दिखा कर अपने पास बुला लेते हैं। जब हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं, तो उन्हें कड़ी हकीकत दिखाई देती है। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन बच्चों के अभिभावकों ने भी एजुकेशन लोन के नाम पर बहुत मोटा लोन ले लिया होता है जिसे उन्हें दो दशक तक चुकाने रहना पड़ता है।

३५

खाद्य बिषार्दी पर जल्द नियंत्रण बेहद आवश्यक

पृथ्वी पर प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन द्वारा प्राप्त होती है, बिना भोजन के ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, परन्तु सभी जीवों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी जरूरत पूरी होते ही भोजन को महत्वहीन समझकर व्यर्थ कर देता है। मनुष्य के पास खाद्य सामग्री के रूप में स्वाद अनुसार चयन के लिए विविध व्यंजन का विकल्प है, जिसका वह अपने हिसाब से उण्डोग करता है। दुनिया में भारत ऐसा देश है, जहां खाद्य बबार्दी और भूख दोनों बड़ी मात्रा में मौजूद है। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अनाज का मोल केवल पैसे से लगाते हैं, जो संपन्न लोग हैं, वे अपने पसंद अनुरूप भोजन पर ज्यादा खर्च करते हैं, तो दूसरी तरफ कुपोषितों को पौष्टिक खाना तो दूर, भर पेट अन्न तक नहीं मिलता। भूख सबकी साधारण एक जैसी होती है, फिर भी अनाज का इतना ज्यादा अपव्यय बेहद दुखिया है।

पराया न किया का दजा नकारात्मा का ननुपुर पानपर दुनिया के हर धर्म में विशेष सन्मान दिया है। भोजन का पहला भोग ईश्वर को लगाते हैं, फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं। किसान फसल बुआई से पहले और फसल कटाई पर ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद स्वरूप त्यौहार मनाते हैं। हमारे समाज में अननदान को सर्वोपरि माना गया है। जीवन देनेवाले भोजन को हम जरूरत के बाद अगर कचरे में फेंक देते हैं तो हमारे लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात है, भोजन प्रकृति द्वारा मनुष्य की कड़ी मेहनत से प्राप्त होता है, इसका मोल उसकी कीमत से परे समझना बहुत जरूरी है। पहले अभिभावक अनाज के हर एक दाने का मोल समझें, फिर अपने बच्चों को भी इसकी अहमियत समझाएं। अनाज को उगाने से लेकर हमारी थाली तक पहुंचाने में अनेक लोगों का संघर्ष जुड़ा होता है, किसान अनाज को उगाने के लिए दिन-रात खेत में मेहनत करता है, अनेक बार प्राकृतिक आपदा और आर्थिक संकट से किसान जूँझता है, इतनी मेहनत के बावजूद भी बहुत बार उनके अनाज को मंडी में योग्य दाम नहीं मिलता। मटियों में संग्रहण हेतु गोदामों के कमी के चलते अनाज खुले में रखने को मजबूर होते हैं, बारिश और खराब मौसम से ऐसा अनाज भीगकर सड़ता है। गोदाम के ऊचत रखरखाव की कमी के कारण हर साल सैकड़ों टन अनाज छूँहे खा जाते हैं, संघर्ष करते हुए अनेक किसान हताश होकर आत्महत्या करते हैं, महाराष्ट्र के मराठवाडा और विदर्भ क्षेत्र में किसानों की आत्महत्याएं ज्यादा दर्ज होती है। हाल ही में संभागीय आयुक्त विभाग की जारी रिपोर्ट अनुसार, मराठवाडा क्षेत्र में 1 जनवरी 2023 से 31 अगस्त 2023 के बीच 685 किसानों ने आत्महत्या की है, जो हमारे आधुनिक एवं उन्नत कहलाने वाले समाज के लिए बेहद शर्मनाक और चिंताजनक बात है।

भारत देश में खाने से पहल ही एक-तिहाई अनाज बर्बाद हो जाता है। यूपीएनईपी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 बताती है कि, भारत में घेरेलू भोजन की बवारी हर दिन 137 ग्राम खाना, सालाना प्रति व्यक्ति लगभग 50 किलोग्राम है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुमानित आंकड़े अनुसार, भारत में 40% खाना

रुपये के बराबर होता है, 30 प्रतिशत सब्जियां और फल कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण समाप्त हो जाते हैं। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं, तो हम उसे उगाने, फसल कटने, परिवहन करने और पैकेज करने में लगने वाली सारी ऊर्जा, पानी, श्रम, प्रयास, निवेश और बहुमूल्य संसाधनों को भी बर्बाद कर देते हैं। सीमित संसाधनों का अनावश्यक विनाश होता है, जिससे ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021, दर्शाती है कि, 61% खाद्य अपशिष्ट घरों से, 26% खाद्य सेवा से और 13% खुदरा से आता है। दुनिया भर में किसी भी अन्य देश की तुलना में चीन और भारत हर साल अनुमानित 92 मिलियन और 69 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक घेरेलू खाद्य अपशिष्ट पैदा करते हैं। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खुलासा किया था कि पांच वर्षों के दौरान (2016 - 2020) केंद्रीय अन्न भंडार में 25,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न बर्बाद हो गया। लोकसभा में अपने लिखित जवाब में यह भी बताया था कि मार्च 2020 से दिसंबर 2021 के बीच लगभग 3,500 मीट्रिक टन अनाज बर्बाद हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, 2022 रिपोर्ट के अनुसार, 224.3 मिलियन लोग या भारत की 16 प्रतिशत आबादी अल्पोपेषित है, जिनमें से 53 प्रतिशत कुपोषित हैं। सभी के लिए पर्याप्त भोजन होने के बावजूद दुनिया में, 690 मिलियन लोग भूखे सोते हैं, जिनमें भारत के 189.2

प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण कुपोषण है। कुछ दिन पहले मैंने देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के भोजनगृह में भोजन करने के लिए भेट दी, विद्यार्थियों के साथ मैं भोजन कर रहा था, भोजन होने के बाद मैं अपनी थाली उठाकर जब आगे बढ़ा तो सामने का नजारा देखकर स्तब्ध रह गया, अनेक विद्यार्थियों ने थाली भरकर भोजन तो लिया लेकिन स्वाद पसंद ना आने के कारण या किसी अन्य कारण से उन्होंने अपनी थालिया वैसी ही अन्न से भरी छोड़ दी थी, जब मैंने वहाँ के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि ऐसा नजारा रोज देखने को मिलता जो बहुत ही दुखद है। देश के कोने-कोने से विद्यापढ़ते आते हैं, सबकी अपनी पसंद और अलग-अलग व्यजन, स्वाद होता है, परंतु थाली में भोजन लेवारे गेज-गेज उसे ऐसा बर्बाद करना कौन-सी शिक्षा है? सिखाती है? अनाज की असली कीमत केवल एमेन्टकश इंसान ही समझ सकता है, जिसने भूख नहीं तकलीफ को समझा है, जिया है, वर्ना आज तो कभी को बड़ी-बड़ी बातें सभी करते हैं लेकिन दूसरे तरफ वही लोग घर, समारोह में खाद्य बबार्दी करते नहीं आते हैं। भारतीय समारोह में तो खाद्य बबार्दी जगहिर है, आखिर कब सुधरेंगे हम? खाना मुझ का हो या खरीदा हुआ, हमें अपनी भूख के हिसाब ही थाली में थोड़ा-थोड़ा भोजन लेना चाहिए, जरूर के अनुसार ही उपभोग होना चाहिए। खाद्य बबार्दी को आगर अपराध मानकर जिम्मेवाली से भारी जुमार्ना वसूला जाएं तो शायद देश एक महीने के अंदर ही खाद्य बबार्दी पूरी तरह

होकर अधिक मात्रा में विकास हो सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, भुखमरी कम होकर समृद्धता बढ़ेगी। समाज के सभी वर्गों को भरपेट अनाज मिलगा, बीमारियां, महागाई कम होंगी, देश आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय रूप से संतुलित होगा। घर, ऑफिस, होटल, रेस्टरेंट, कार्यक्रम, सामूहिक समारोह, संस्थान, भोजनालय, ढाबे, कैफे दुकान, मॉल, गोदाम, कोल्ड-स्टोरेज अर्थात् हर वो जगह जहाँ खाद्य सामग्री हो, चाहे निजी हो या सरकारी विभाग, खाद्य बाबार्दी पर जिम्मेदार व्यक्ति पर डंड वसूला जाए तो हम जल्द सुधर जायेंगे। लोग जागरूक होकर भोजन सिमित मात्रा में पकाएंगे, समारोह में लोग खाना चखने के बाद स्वाद पसंद आने पर ही सिमित मात्रा में खाना थाली में परोसेंगे, इससे कुपोषण खत्म होने में मदद, उत्तम स्वास्थ्य, चटोरेपन पर लगाम लगेगी। किसी कारणवश फिर भी अन्न बच जाने पर खाना सार्वजनिक फूड स्टाल को भेट किया जाए। हर शहर, गांव, कस्बों में भोजन संग्रहण के लिए ऐसे फूड स्टाल केंद्र होने चाहिए, जहाँ पर शेष भोजन को दिया जा सके। ऐसे केंद्र पर जरूरतमदां के लिए सुविधानुसार मुफ्त भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ कोई भी भूखा व्यक्ति जाकर भरपेट खाना खा सकता है। इस व्यवस्थापन से न कोई भूखा होगा, न अनाज की बाबार्दी होगी, सिर्फ हर ओर समृद्धि होगी, कीमती जिंदगियां बचाई जाएंगी, सबको अन्न के हर दाने का मोल समझेगा और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या का विकास के रूप में परिवर्तन होगा।

अब खत्म होना चाहिए कावेरी जल विवाद

कर्नाटक और तमिलनाडू के बीच कावेरी नदी का संतुलन होना चाहिए।

जीवनरखा मानी जाती है। कावरी दोनों राज्यों करोड़ों लोगों के लिए वरदान है, लेकिन निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते कर्नाटक और तमिलनाडू की जनता के बीच केवल अगज्ञ और हिंसा के ही नहीं, सांस्कृतिक टकराव हालात भी उत्पन्न होने के आसार नजर आने लगे हैं। सनातन भारतीय संस्कृति में पानी पिलायुण्य का श्रेष्ठ काम माना जाता है। दरअसल तमिलनाडू में इस साल कम बारिष होने के कारण पानी की जबरदस्त किलत है। कम बारिष कारण राज्य में चालीस हजार एकड़ में खफसल बर्बाद हो रही है, इसलिए उसे कृशि और किसानों की आजीवका के लिए तुरंत पानी देज जरूरत है। इसी जरूरत के महेनजर पांच हजार घन मीटर पानी देने का फैसला दिया गया। लेकिन कर्नाटक इतना पानी देने को भी तैयार नहीं है।

भारत में नदियों के जल बंटवारा, बांधों का निर्माण और राज्यों के बीच उसकी हिस्सेदारी एक गंभीर व अनसुलझी रहवाली समस्या बनी हुई है। इसका मुख्य कारण



प्रारंत हाकर नांदया के जल का दाहन करना है। कर्नाटक में जल विवाद के सामने आते ही इस मुद्दे पर लड़ाई जीतने के लिए राजनीतिक दल और किसान संगठन एक गाय हो जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडू के किसान एक साल में तीन फसल उगा रहे हैं, जबकि कर्नाटक के पास एक फसल के लिए भी पानी कम पड़ता

कनाटक-तामिलनाडू के बाच कावरा जल विवाद 124 साल से स्थाई समस्या बना हुआ है।

दक्षिण भारत की गंगा मानी जाने वाली कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडू में बहने वाली जीवनदायी सदानीरा नदी हैं। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि पर्वत से निकली है।

दोनों राज्यों के हिस्सों में खेती होती है। तमिल भाषा में कावेरी को ह्यापोनीह्य कहते हैं। पोन्नी का अर्थ सोना उगाना है। दोनों राज्यों की स्थानीय आबादी में ऐसी लोकमान्यता है कि कावेरी के जल में धूल के कण मिले हुए हैं। इस लोकमान्यता को हम इस अर्थ में ले सकते हैं कि कावेरी के पानी से जिन खेतों में सिंचाई होती है, उन खेतों से फसल के रूप में सोना पैदा होता है। इसीलिए यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। बहुगिरी पर्वत कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में आता है, जो कर्नाटक के अस्तित्व में आने से पहले मैसूरु राज्य में था। यहाँ से यह नदी मैसूरु राज्य को सिंचित करती हुई दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई तमिलनाडु में प्रवेष करती है और फिर इस राज्य के बड़े भू-भाग को जल से अभिसिंचित करती हुई बंगल की खाड़ी में गिरती है।

1892 व 1924 में मैसूर राज्य व मद्रास प्रेसीडेंसी, वर्तमान तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौते हुए थे। आजादी के बाद मैसूर कर्नाटक में विलय हो गया। इसके इसलिए हम पानी नहीं देंगे। कर्नाटक का तर्क है कि अंग्रेजों के शासनकाल में कुर्ग मैसूर रियासत का हिस्सा था, और तमिलनाडु मद्रास प्रेसीडेंसी के रूप में फिरंगी हुकूमत का गुलाम था।

तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य ?

तूल पकड़ता जा रहा है। और कर्नाटक में लोग पानी के प्रदर्शन कर रहे हैं। कावेरी द के चलते मंगलवार को बंद रहा। इसके साथ ही अरियों ने आज 29 सितंबर पूरे राज्य में बंद करने आह्वान किया। यह बंदी एक दिन की है। लगभग 140 साल पुरानी है। मामला नियमी अदालतों से लेकर देश की उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा लेकिन विवाद खत्म नहीं हो सका। कावेरी नदी कर्नाटक के को डागू जिले से निकलती है और तमिलनाडु पे पुपुचेरी से होती हुई बंगल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी गुजरती हुई तमिलनाडु से बंगल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी बैसिन का कुल जलसंभरण (वाटरशेड) 81,155 वर्ग किलोमीटर है जिनमें से कर्नाटक में नदी का जल संभरण क्षेत्र सबसे ज्यादा लगभग 34,273 वर्ग किलोमीटर है। केरल में कुल जल संभरण क्षेत्र 2,866

कुछ करने की ललक है तो वे नाम भी रोशन उन्होंने 469.6 अंक हासिल कर विश्व माणिनी सरीखी पदकवीर बेटियों का नाम पुराने

उन्हें हैससे की ज़रूरत है। मैं आयोजित हो रहे एशियन ग्रीष्मीयन की बेटियों ने हर हिंदुस्तानी को अपसर प्रदान किया है। बेटी हो या नॉर्मल परिवार से हुंहुंची लड़की हो। सभी आपनी हुए मेडल जीत रही हैं। सिपट 50 मीटर राइफल की नई एशियाई चैम्पियन बनी विश्व चैम्पियन भी हैं, क्योंकि वह दियु रिकॉर्ड और एशियन

पोजिशन में, त पदक जीता ली, सभी वर्गों आज हैं। सिपट पदक हासिल खेलों का वैथा द खुशगावर है। सिपट के रिया सांगवान स्टर्ल की टीम भी विजेताओं की श्रीणि में रखा जाएगा। भारत की इन सामान्य-सी बेटियों ने आसमान छूकर हामां भारतीहाल को सम्मानित किया है और खुट को हाअमाधारणल साकित किया है। एशियन खेल या राष्ट्रमंडल खेलों के मुकाबले हों अथवा विश्व चैपियनशिप, ओलंपिक के मैदान हों, खेलों में प्रतिद्वंद्विता गला-काट होती है। एक-एक अंक के लिए जद्देजहद की जाती है। भारत की बेटी सिपट ने, 7.3 अंकों के फासले से चीरी गिलाडी को मात ढेकर विश्व

यह गगनचुबी सफलता और उपलब्धि है जैसे गौरतलब तो यह है कि फरीदकोट (पंजाब) के एक किसान घर और घावल का कारोबार करने वाले परिवार की बेटी सिपट की प्राथमिकता निशानेबाजी नहीं थी। वह एक बीवीएस की छात्रा है। जाहिर है कि डॉक्टर साहिबा बनने की राह पर हैं, लिहाजा सिपट खुद को ह्याकार्सिम्पक निशानेबाज़ार मानती है। मेडिकल से मेडल तक की यात्रा 22 वर्षीय बेटी के लिए बड़ी असमंजस भर्ती द्वारा लेकिन सिपट ने मातृ-पितृ तंत्रों को बदल दिया।

